मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर राजस्व प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से जनता को लाभ मिलेगा • हिन्दुस्तान

सीएम ने शुरू की राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली

जमीन-जायदाद के केस अब ऑनलाइन

लखनऊ | विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को पारदर्शी व आसान व्यवस्था सुलभ कराने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा विभाग है और इसकी कार्यप्रणाली को जितना अधिक कम्प्यूटरीकृत व पारदर्शी बनाया जाए उतना ही जनता को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करते हुए कही। इस व्यवस्था से नायब तहसीलदार से उच्च स्तर तक के सभी राजस्व न्यायालयों के मामले ऑनलाइन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी व विभाग को बधाई देते हुए कहा कि जनता को सुविधा पहुंचाने के नजरिए से अभी और अधिक कदम उठाने की जरूरत है।

यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैसले लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। छात्र-छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप योजना से जिन घरों में लैपटॉप उपलब्ध हो रहे हैं, वहां कम्प्यूटरीकृत योजनाओं का लाभ लेना और आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के साथ हुई वार्ता व अमेरिकी निवेशकों के सूबे में निवेश के प्रति रुचि दिखाने से साफ है कि राज्य में विकास के लिए बेहतर वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को वह अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। राजस्व मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग के कम्प्यूटरीकरण का काम 14 साल से अटका हुआ था। असल में लेखपाल व पेशकार नहीं चाहते थे कि नई व्यवस्था लागू हो और उनका दखल कम हो। कम्प्यूटीकरण व ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता

क्या है खासियत

- इस व्यवस्था के तहत लोगों को घर बैठे राजस्व वादों के हस्ताक्षरित फैसलों की प्रति उपलब्ध होगी
- मुकदमे की तारीख व अन्य आवश्यक जानकारी मिल सकेगी
- पहले चरण में यह व्यवस्था प्रदेश के 18 मण्डलों के मण्डलीय राजस्व न्यायालयों और 25 जनपदों में लागू
- अप्रैल, 2013 के अंत तक बाकी सभी जनपदों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा

एक क्लिक पर मिल जाएगी तारीख

बस्ती | निज संवाददाता

राजस्व न्यायालयों को बुधवार को ऑनलाइन कर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में उद्घाटन किया। एनआईसी में कमिश्नर, जिलाधिकारी समेत राजस्व से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे।

राजस्व न्यायालयों के आनलाइन हो जाने से वादकारियों को अब तारीख से लेकर मुकदमे का स्टेटस जानने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। राजस्व न्यायालयों में कामकाज का तरीका और आधुनिक हो गया। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के तहत सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने के साथ संदेश दिया है, ऑनलाइन होने से एकतरफ जहां मुकदमों की मानीटरिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी, वहीं वादकारियों को भी अब काफी सहूलियतें मिल जाएंगी। इस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करते हुए लोकहितकारी बनाने का हरसम्भव प्रयास किया जाए।राजस्व न्यायालयों के ऑनलाइन हो जाने से उच्चाधिकारियों के लिए राजस्व मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया की मानीटरिंग करने में आसानी हो जाएगी। एनआईसी में सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी अनिल कुमार ढमेले, अपर जिलाधिकारी राम एकबाल सिंह, एसडीएम सदर के बालाजी, एनआईसी के सूचना विज्ञान अधिकारी यूबी मल्ल मौजूद रहे।

ऑनलाइन राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन

Commissioner Basti, DM Basti and Revenue officers attended the VC during Inauguration of Revenue court computerization